the Ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) The number of job-seekers, all of whom are not necessarily unemployed, who were on the live register of employment exchanges in the country at the beginning of the Eighth Five Year Plan was 365.5 lakhs.

(b) 7.5 lakh job-seekers were placed in employment through the employment exchanges in the country during the period from 1.4.92 to 31.8.95.

(c) and (d) The employment strategy of the Eighth Plan has been formulated as part of 10-year medium term perspective of achieving the goal of near full employment by the year 2002. The Eighth Plan strategy envisages generation of additional employment opportunities of the order of 8.5 million per year, on an average, through faster growth of employment intensive sectors, subsectors and activities like agriculture, agro and rural industries, rural infrastructure, small and decentralised manufacturing sector, urban informal sector and services. The registered unemployed are aso likely to benefit from this. A continuation of the Eighth Plan strategy in the period 1997-2002 is expected to progressively increase employment levels to take care of the backlog of unemployment at the beginning of the Eighth Plan and the additions to labour force during the Eighth Plan (35 million) and in the period 1997-2002 (36 million) and attain the goal of near full employment by 2002.

कोयला परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहयोग की मांग

1397. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ कोयला परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ विदेशी कंपनियों से सहयोग मांगा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इस सहयोग की निबंधन और शर्तें क्या-क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि कोयला क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं के विलम्ब का कारण अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित लालफीताशाही है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा इस कार्यवाही की गयी है, और

(ग) इस संबंध में तथागत ब्यौरे क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) चालू परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए किसी भी विदेशी कंपनी से कोई सहायता नहीं मांगी जा रही है । तथापि, दिनांक 1.12.1995 को कोल इंडिया लि. (कों.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) में बहुपक्षीय /द्विपक्षीय सहयोग करारों के एक भाग के रूप में विदेशी कंपनियों के तकनीकी एंव वित्तीय सहायता से 10 परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन है ।

(ख) और (ग) कोयला क्षेत्र में परियोजनाओं में अधिक समयावधि लगने के मुख्य कारण निम्न है- भूमि अधिग्रहण और सम्बद्ध पुनर्वास समस्याओं में विलम्ब, विपरीत भू-खनन परिस्थितियों, उपकरणों की आपूर्ति में विलंब और "टर्न-की" निष्पादन में विलंब और निधि संबधी व्यवधान । ऐसी परियोजनांए जहां कि लागत अधिक आती है, संशेधित लागत अनुमानों को बनाए जाते समय गइराई से मदवार लागत वृद्धि को उनके कारणों सहित समीक्षा की जाती है, जोकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है । जिम्मेवारी का प्रश्न तब उठेगा जबकि परियोजना के योजनकर्ताओं अथवा परियोजना क्रियान्वयन अधिकारियों के कारण कोई गलती हो जाती है । किसी भी व्यक्ति विशेषकर लापरवाही होने के संबध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है ।

खाद्यान्नों का बफर स्टाक

1398. **श्री अजीत जोगी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1995 तक खाद्यान्नों का कुल भंडार कितना था,

(ख) प्रत्येक श्रेणी में वर्तमान स्टाक की स्थिति क्या है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्टाक के वर्तमान स्तर को घटाने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) पहली जुलाई 1995,पहली अक्तूबर, 1995 और पहली

नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक निम्नानुसार था:-

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

	1.7.95 की स्थिति के अनुसार (अनन्तिम)	1.10.95 की स्थिति के अनुसार	1.11.95 की स्थिति के अनुसार
गेंहू	19.17	16.78	15.77
चावल	16.44	13.00	12.41
जोड़	35.61	29.78	28.18

(ग) और (घ) बफर स्टाक रखने संबधी वर्तमान नीति के अनुसार उपर्युक्त सरकार द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम बफर मानदंडों से कहीं अधिक है ।

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

तारीख	गेंहू	चावल	जोड़
पहली अप्रैल	3.7	10.8	14.5
पहली जुलाई	13.1	9.2	22.3
पहली अक्तूबर	10.6	6.0	16.6
पहली जनवरी	7.7	7.7	15.4

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने में उपयोग करने के अलावा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अधिशेष स्टाक का जवाहर रोजगार योजना, पोषाहार काय्रक्रम, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हास्लों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा चलाई जा रही खाद्य विधायन यूनिटों, माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और इसकी फ्रेन्चाइज्ड यूनिटों तथा मिड-डे-मील स्कीम जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन उपयोग किया जाए । इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम घरेलु खपत और निर्यात के प्रयोजन के लिए गेंहूं और चावल की खुली बिक्री कर रहा है। खाद्यान्नों के बफर स्टाक पर रख-रखाव लागत के प्रति खर्च को कम करने की आवश्यकता अधिशेष स्टाक में कमी लाने के मुख्य कारण है ।

Proposal for auction Platforms for Bid! Tobacco in Andhra Pradesh

1399. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to set up auction platforms for tobacco in Andhra Pradesh by the Tobacco Board;

(b) if so, the proposed, location of such platforms; and

(c) whether this proposal would benefit a large number of farmers in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir. There is no proposal to set up new auction platforms for tobacco in Andhra Pradesh. However, during 1994-95, 19 auction platforms were operated in Andhra Pradesh by the Tobacco Board.

(b) and (c) Does not arise.

Request of Additional Quota of Wheat etc.

1400. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether request have been received from the State Governments for enhancement of their quota of wheat, rice, sugar etc.;

(b) if so, the details thereof;

(c) the action taken thereon; and

(d) the manner in which the demands of the States are to be met in 1996?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) During 1995, requests have been received from the State Governments/UT Administrations of Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Kamataka, Kerala, Maharashtra,